

बॉण्ड यील्ड/प्राप्ति

प्रलिस के लयः

बॉण्ड यील्ड/प्राप्ति, [राज्य वकलस ःण](#), [भारतीय रज़रव बैंक](#), [सरकारी प्रतभूतयऱँ](#)

मेन्स के लयः

बॉण्ड यील्ड/प्राप्ति, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना से संबंघतऱँ मुददे ।

[स्रोतः द हद्वऱँ](#)

चरूा में क्यूँ?

हाल ही में राज्य सरकारों ने [राज्य वकलस ःण](#) बॉण्ड की नीलामी के माध्यम से **रकऱँरूड 50,206 करोड रुपए जुटाए** हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी साप्ताहकऱँ उधारी है ।

- [भारतीय रज़रव बैंक](#) के आँकड़ों के अनुसार, जुटाई गई धनराशऱँ इस अवधऱँ के लयऱँ नरऱँधारतऱँ 27,810 करोड रुपए के सांकेतकऱँ उधार लक्ष्य से कहीं अधकऱँ है । यह वतऱँतीय बाज़ारों में राज्य सरकार की प्रतभूतयऱँ की प्रबल मांग का संकेत देता है ।
- SDL [सरकारी प्रतभूतयऱँ](#) का हसऱँसा है, जहाँ राज्य सरकारें बाज़ार से ःण जुटाती हैं । SDL केंद्र सरकार द्वारा जारी दनऱँंकतऱँ प्रतभूतयऱँ के लयऱँ आयोजतऱँ नीलामयऱँ के समान सामान्य नीलामी के माध्यम से जारी की गई दनऱँंकतऱँ प्रतभूतयऱँ हैं ।

बॉण्ड क्यूँ हैं?

- **परचयः**
 - बॉण्ड **पैसे उधार लेने का एक साधन** है । यह एक IOU (I owe you अर्थात् मैं आपका ःणी हूँ) की तरह है ।
 - IOU ःण की एक लखऱँतऱँ **स्वीकृतऱँ** है जो एक पक्ष पर दूसरे पक्ष का बकाया है । IOU प्रॉमसऱँरी नोट्स की तुलना में कम औपचारकऱँ और वैधानकऱँ रूप से बाधयकारी है ।
 - **कसऱँी देश की सरकार** या कसऱँी कंपनी द्वारा धन जुटाने के लयऱँ एक बॉण्ड जारी कयऱँ जा सकता है ।
 - चूँकऱँ [सरकारी बॉण्ड](#) (भारत में **G-सेक**, अमेरऱँका में ट्रेज़री और यूके में गलऱँट्स के रूप में संदर्भतऱँ) **संप्रभु गारंटी** के साथ आते हैं, उन्हें सबसे सुरक्षतऱँ नवऱँशों में से एक माना जाता है ।
- **सरकारी प्रतभूतयऱँ के प्रकारः**
 - **ट्रेज़री बलऱँ (T-बलऱँ)**: ट्रेज़री बलऱँ शून्य कूपन प्रतभूतयऱँ हैं और कोई ब्याज नहीं देते हैं । इसके बजाय उन्हें छूट पर जारी कयऱँ जाता है और परपऱँकवता पर अंकतऱँ मूल्य पर प्रतदऱँय कयऱँ जाता है ।
 - **नकदी प्रबंधन बलऱँ (CMB)**: वर्ष 2010 में, भारत सरकार ने RBI के परामर्श से भारत सरकार के नकदी प्रवाह में अस्थायी वसऱँगतयऱँ को ठीक करने के लयऱँ एक नया अल्पकालकऱँ साधन पेश कयऱँ, जसऱँ CMB के रूप में जाना जाता है ।
 - CMB में T-बलऱँ का सामान्य चरतऱँर होता है लेकनऱँ ये 91 दनऱँों से कम की परपऱँकवता अवधऱँ के लयऱँ जारी कयऱँ जाते हैं ।
 - **दनऱँंकतऱँ सरकारी प्रतभूतयऱँ (G-Secs)**: दनऱँंकतऱँ **G-Secs** ऐसी प्रतभूतयऱँ हैं जनऱँमें एक नशऱँचतऱँ अथवा फ्लोटऱँग कूपन दर (ब्याज दर) होती है जसऱँका भुगतान अर्ध-वार्षकऱँ आधार पर अंकतऱँ मूल्य पर कयऱँ जाता है । सामान्यतः दनऱँंकतऱँ प्रतभूतयऱँ की अवधऱँ 5 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है ।
 - **राज्य वकलस ःण (SDLs)**: राज्य सरकारें भी बाज़ार से ःण जुटाती हैं जनऱँमें SDL कहा जाता है । SDL केंद्र सरकार द्वारा जारी दनऱँंकतऱँ प्रतभूतयऱँ के लयऱँ आयोजतऱँ नीलामयऱँ के समान सामान्य नीलामी के माध्यम से जारी की गई दनऱँंकतऱँ प्रतभूतयऱँ हैं ।

Government Securities (G-Sec)



Types of Government Securities

■ बॉण्ड यील्ड:

- किसी बॉण्ड यील्ड उसके द्वारा अर्जति रटिर्न की प्रभावी दर है। लेकिन रटिर्न की दर नश्चिति नहीं है- यह बॉण्ड की कीमत के साथ बदलती रहती है।
- लेकिन इसे समझने के लिये पहले यह समझना होगा कि बॉण्ड कैसे संरचित होते हैं।
- प्रत्येक बॉण्ड का एक अंकित मूल्य और एक कूपन भुगतान होता है। बॉण्ड की कीमत भी होती है, जो बॉण्ड के अंकित मूल्य के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी।
- अंकित मूल्य एवं कूपन भुगतान के अतिरिक्त बॉण्ड में एक कूपन दर भी होती है।
 - कूपन दर बॉण्ड के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की गई नश्चिति वार्षिक ब्याज दर है।
 - उदाहरण के लिये, 10-वर्षीय G-sec का अंकित मूल्य 100 रुपए है और इसका कूपन भुगतान 5 रुपए है तथा कूपन दर 5% है।
- इस बॉण्ड के खरीदार सरकार को 100 रुपए (अंकित मूल्य) देंगे; बदले में, सरकार उन्हें अगले 10 वर्षों तक प्रतिवर्ष 5 रुपए (कूपन भुगतान) का भुगतान करेगी, तथा अंत में उनके 100 रुपए को वापस कर देगी।
 - इस बॉण्ड पर 5 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर या उपज है। अभी 100 रुपए छोड़ने और एक दशक तक इसे अपने अधिकार से दूर रखने के लिये नविशक को पुरस्कृत करना प्रतफल है।

■ यील्ड करव:

- यील्ड करव वभिन्न परपिक्रवता अवधि के लिये ऋण पर ब्याज दरों का एक चतिरमय प्रतिनिधित्व है।
- यह दर्शाता है कि यदि कोई नविशक एक नश्चिति अवधि के लिये अपना पैसा उधार देता है तो वह कतिना प्रतफल अर्जति करने की उम्मीद कर रहा है।
- एक नश्चिति आय वशिलेषक उपज वक्र का उपयोग एक प्रमुख आर्थिक संकेतक के रूप में कर सकता है, खासकर जब यह उल्टे आकार में बदल जाता है, जो आर्थिक मंदी का संकेत देता है, क्योंकि दीर्घकालिक रटिर्न अल्पकालिक रटिर्न से कम होता है।

RBI बॉण्ड यील्ड का प्रबंधन कैसे करता है?

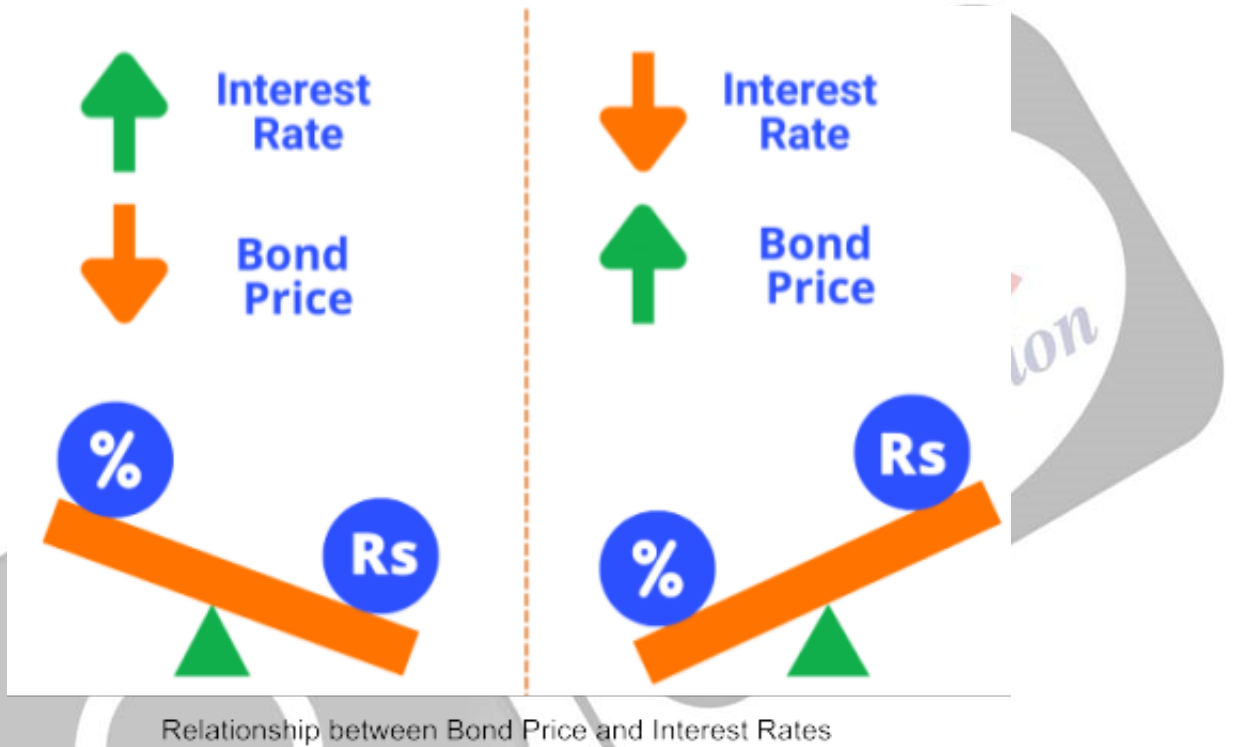
- भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) बॉण्ड यील्ड को प्रबंधित करने और अर्थव्यवस्था के भीतर मौद्रिक स्थितियों को वनियमित करने के लिये ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में नयोजित करता है। OMO के माध्यम से, RBI रणनीतिक रूप से खुले बाज़ार में सरकारी प्रतभूतियों (G-secs) को बेचता या खरीदता है।
- जब RBI का लक्ष्य अतिरिक्त तरलता पर अंकुश लगाना और मुद्रासफीतिके दबाव को कम करना होता है, तो वह बाज़ार से तरलता को प्रभावी ढंग से अवशोषित करते हुए G-secs बेचता है। इसके विपरीत, आर्थिक गतिविधिके प्रोत्साहित करने तथा तरलता को बढ़ाने के लिये RBI सिसिम में धनराशि डालते हुए सरकारी प्रतभूतियों को वापस खरीदता है।
 - जब RBI जी-सेक बेचता है, तो बॉण्ड यील्ड पर दबाव पड़ता है, जिससे उधार लेना महंगा हो जाता है और इस तरह अत्यधिक उधार लेने तथा व्यय पर अंकुश लगता है।
 - इसके विपरीत, सरकारी प्रतभूतियों की खरीद से बॉण्ड की कीमतें अधिक हो जाती हैं, जिससे बॉण्ड यील्ड कम हो जाती है, जिससे उधार लेने और नविश को प्रोत्साहन मिल सकता है।
- OMO के साथ मलिकर, RBI रेपो दर, नकद आरकषति अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात सहित मौद्रिक नीति उपकरणों का एक सूट नयोजित करता है।
 - इन उपकरणों को रणनीतिक रूप से तैनात करके, RBI बॉण्ड यील्ड के प्रबंधन और विकास तथा स्थिरता के लिये अनुकूल स्थिर आर्थिक स्थितियों को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण का आयोजन करता है।

उपज वक्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?

■ बाज़ार की मांग और बॉण्ड की कीमतें:

- कल्पना कीजिये कि केवल एक बॉण्ड उपलब्ध है और दो खरीदार इसे खरीदना चाहते हैं। वे एक-दूसरे के वरिद्ध बोली लगा सकते हैं, जिससे बॉण्ड की कीमत बढ़ जाएगी।

- भले ही बॉण्ड का अंकित मूल्य 100 रुपए ही रहता है, यदि इसे 110 रुपए में बेचा जाता है, तो यील्ड कम हो जाती है, क्योंकि कूपन भुगतान 5 रुपए पर स्थिर रहता है। इसलिये बॉण्ड के लिये भुगतान की गई कीमत के आधार पर यील्ड की प्रभावी गणना की जाती है।
- **अर्थव्यवस्था की ब्याज दर के साथ संरेखण:**
 - यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बॉण्ड के प्रारंभिक कूपन भुगतान से भिन्न है, तो बाज़ार की ताकतें मौजूदा ब्याज दर के साथ संरेखित करने के लिये बॉण्ड यील्ड को समायोजित करती हैं।
 - उदाहरण के लिये, यदि अर्थव्यवस्था की ब्याज दर 4% है और कोई बॉण्ड 5% उपज प्रदान करता है, तो कई निवेशक उच्च रटिर्न हेतु इसे खरीदने के लिये भीड़ बढ़ जाती है।
 - यह मांग बॉण्ड की कीमत को तब तक बढ़ाती है जब तक कि इसकी यील्ड अर्थव्यवस्था की ब्याज दर से सुमेलित नहीं है।
 - इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था की ब्याज दर बॉण्ड यील्ड से अधिक है, तो बॉण्ड की कीमत तब तक कम हो जाती है जब तक कि इसकी यील्ड प्रचलित दर से सुमेलित नहीं है।
 - **समानता:** यदि अर्थव्यवस्था की ब्याज दर बॉण्ड यील्ड से अधिक है, तो यह अर्थव्यवस्था की ब्याज दर के पक्ष में भारी भार होने जैसा है। इससे अर्थव्यवस्था की ब्याज दर पक्ष की ओर झुकाव होता है, जो दर्शाता है कि बॉण्ड यील्ड ब्याज दर के सापेक्ष कम है।
 - इसके विपरीत, यदि बॉण्ड यील्ड अर्थव्यवस्था की ब्याज दर से अधिक है, तो यह बॉण्ड यील्ड के पक्ष में अत्यधिक भार रखने जैसा है। यह बॉण्ड के प्रतफल पक्ष की ओर झुकाव रखता है, जो दर्शाता है कि बॉण्ड की प्रतफल ब्याज दर के सापेक्ष अधिक है।



बॉण्ड यील्ड के सख्त होने का क्या असर होगा?

- **बैंकों और म्यूचुअल फंडों को नुकसान:**
 - सरकारी प्रतभूतियों (g-sec) रखने वाले बैंकों और म्यूचुअल फंड दोनों को बॉण्ड की कीमतों तथा यील्ड के बीच विपरीत संबंध के कारण नुकसान होगा। जैसे-जैसे बॉण्ड की यील्ड बढ़ती है, बॉण्ड की कीमतें गिरती हैं, जिससे इन संस्थानों को मार्क-टू-मार्केट घाटा होता है।
- **ऋण लागत में वृद्धि:**
 - सरकारी प्रतभूतियों पर उच्च प्रतफल का अर्थ है कि सरकार को नवीन ऋण पर उच्च ब्याज दरों की पेशकश करनी होगी। सरकारी ऋण लेने की लागत में इस वृद्धि का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कॉर्पोरेट्स के लिये उच्च ब्याज दरें और बैंकों के लिये संभावित रूप से उच्च ऋण दरें हो सकती हैं, जिससे व्यवसायों तथा व्यक्तियों के लिये उधार लेने की लागत प्रभावित हो सकती है।
- **कॉर्पोरेट बॉण्ड पर प्रभाव:**
 - बाज़ार में बढ़ती बॉण्ड यील्ड के बीच निवेशकों को आकर्षित करने के लिये कॉर्पोरेट्स को अपने बॉण्ड पर ब्याज दरें बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे कंपनियों के लिये ऋण लेने की लागत बढ़ सकती है, जिससे संभावित रूप से उनकी लाभप्रदता और निवेश नर्णय प्रभावित हो सकते हैं।
- **इक्विटी बाज़ार पर प्रभाव:**
 - जैसे-जैसे बॉण्ड की संख्या बढ़ती है, इक्विटी में निवेश की अवसर लागत बढ़ जाती है क्योंकि स्टॉक की तुलना में निश्चित आय वाली प्रतभूतियाँ अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक हो जाती हैं। निवेशक अपने आवंटन को इक्विटी से हटाकर बॉण्ड की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं जिससे स्टॉक की मांग और संभावित रूप से इक्विटी की कीमतों में भी कमी आएगी।

?????????:

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, नमिनलखिति में से कौन-सा/से गैर-वत्तितय ऋण में सम्मलिति है? (2020)

1. परविरों का बकाया गृह ऋण
2. क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशा
3. राजकोष बलि

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. भारतीय रज़िर्व बैंक भारत सरकार की प्रतभूतयिों का प्रबंधन और सेवाएँ प्रदान करता है, लेकनि कसिी राज्य सरकार की प्रतभूतयिों का नहीं ।
2. भारत सरकार कोष-पत्र (ट्रेज़री बलि) जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष-पत्र जारी नहीं करती ।
3. कोष-पत्र ऑफर अपने समतुल्य मूल्य से बट्टे पर जारी कयि जाते हैं ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, 'खुला बाज़ार प्रचालन' कसिे नरिदषिट करता है? (2013)

- (a) अनुसूचति बैंकों द्वारा RBI से ऋण लेना
- (b) वाणजियकि बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना
- (c) RBI द्वारा सरकारी प्रतभूतयिों का क्रय और वकिरय
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)